

# राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की खेती का भौगोलिक प्रभाव

Pappu Lal Kumawat

Assistant Professor Geography  
Govt. Girls College Bassi, Chittorgarh.

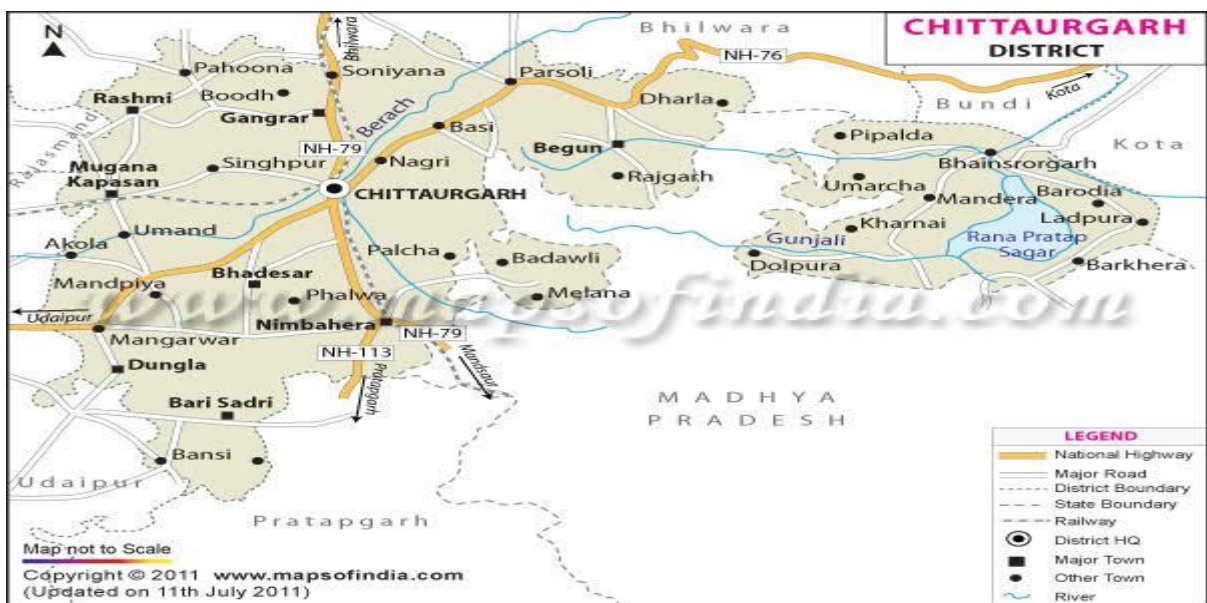
सार—

चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति, मृदा, जलवायु, इस फसल के अनुकूल है। अफीम (पेपवर सोमनिफरम एल.) एक नकदी फसल है लेकिन इसे उगाने का उद्देश्य औषधीय है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की अनुमति और मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम की खेती को विनियमित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ही इस उत्पाद की स्वयं एवम् एकमात्र खरीददार है। भारत में इसकी कृषि अफीम व बीजों के लिए की जाती है। अफीम, पोस्त के डोडो से प्राप्त होती है। भारत में अफीम की खेती मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों के अधिसूचित इलाकों में ही की जाती है। नारकोटिक्स की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (बच्च), ग्वालियर (मध्यप्रदेश) द्वारा अफीम की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस जारी किये जाते हैं। राजस्थान अफीम उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के झालावाड़, बांरा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिलों के अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है।

कुंजीशब्द: अफीम की खेती समुद्र तल, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, अनुज्ञप्ति सरकार ।

प्रस्तावना—

चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। जिले का अक्षांशीय विस्तार 23032' से 25013' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 74012' से 75049' पूर्वी देशान्तर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 10856 वर्ग किमी तथा समुद्रतल से ऊँचाई 487 मीटर है। यहाँ लाल, काली एवं लाल-काली मिट्टियाँ पाई जाती है। कुल क्षेत्रफल के 18.8 प्रतिशत पर वन है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क है तथा औसत वार्षिक वर्षा 841.5 मिलीमीटर है। जिले में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 480882 हैक्टेयर है जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 39.69 प्रतिश है। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार रबी की तथा गेहूँ, सरसों, गन्ना खरीफ की प्रमुख फसले हैं। व्यवसायिक फसलों में अफीम यहाँ की प्रमुख फसल है। उक्त अफीम की फसल के लिए भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा कृषकों के लिए प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।



जिले का अक्षांशीय विस्तार 23032' से 25013' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 74012' से 75049' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। काली, लाल एवम लाल-काली मृदा तथा उष्टकटिबन्धय शुष्क जलवायु जिले में पायी जाती है। अफीम की खेती रबी में अक्टूबर-नवम्बर से फरवरी-मार्च माह के मध्य में की जाती है। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के समय 20 से 25 के मध्य तापमान होना चाहिए। अफीम की बुवाई छिड़काव विधि से या कतारों में की जाती है। अफीम के लिए मृदा के गुणवत्ता (भारी या हल्की मृदा) के अनुसार 8 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है।

### शोध के उद्देश्य-

- अफीम की कृषि का चित्तौडगढ़ जिले में गहन अध्ययन ।
- जिले में अफीम व अन्य फसलों की लागत व आय का तुलनात्मक अध्ययन।
- जिले में अफीम की कृषि में संलग्न कृषक परिवारों की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि व प्रभावों का अध्ययन तथा कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण।
- समय-समय पर जारी अफीम नीति का अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभाव ।

### परिकल्पना-

अफीम नगदी फसल उत्पादित करने वाले कृषकों का आर्थिक, सामाजिक स्तर अन्य नकदी फसलों के उत्पादकों से अधिक सृद्ध होता है। उक्त परिकल्पना के आधार पर अफीम के आर्थिक - सामाजिक प्रभावों के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभावों का आनुभविक अध्ययन।

### अध्ययन विधितंत्र-

अफीम के अनुज्ञप्तिधारियों का प्रतिदर्श बनाने हेतु बहुचरणी प्रतिचयन (डनसजपेजंहम उचसपदह) प्रक्रिया, साक्षात्कार तथा द्वितीय आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

### विपणन-

अफीम दूध का मूल्य केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा मॉर्फिन की मात्रा के आधार पर, जो कि 1700 से 2500 रुपये प्रति किलोग्राम तक तथा गैर कानूनी रूप से लाखों रुपये प्रति किलोग्राम तक।

### अध्ययन क्षेत्र में अफीम की कृषि-

अफीम की कृषि पर अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी अफीम नीति का इसमें उत्पादन व वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विगत वर्षों में अफीम कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी आयी है। 2008 में पोस्त की खेती में संलग्न क्षेत्र 26000 हैक्टेयर था जो 2018 में घटकर 5800 हैक्टेयर रह गया। तथा अनुज्ञप्तिधारी किसानों की संख्या भी जो 2008 में 1.60 लाख थी, जो घटकर 2018 में 70,000 से 80,000 ही रह गयी। राजस्थान में वर्ष 2009 में 3595 हैक्टेयर में अफीम खेती थी तथा इस वर्ष उत्पादन 211 मिट्रिक टन था जो वर्ष 2010 में क्षेत्रफल 5700 है। तथा उत्पादन 337 मीट्रिक टन हुआ। ऐसा काश्तकारों के अधिक लाइसेंस व खेती के रकबा बढ़ाने से सम्भव हो पाया। लेकिन फिर भी राजस्थान में अफीम काश्तकारों की संख्या व रकबा में तेजी से कमी आयी है। वर्ष 2017-18 में अफीम के रकबे से वर्ष 1989-90 का रकबा करीब पौने छह गुना अधिक था। वहीं काश्तकारों की संख्या भी करीब तीन गुनी थी। अध्ययन क्षेत्र को नारकोटिक्स विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए तीन खण्डों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है :-

प्रथम खण्ड	द्वितीय खण्ड	तृतीय खण्ड
भदेसर	गंगरार	निम्बाहेड़ा
चित्तौड़	राशमी डूंगला	बडी सादडी
वल्लभनगर	मवली भूपालसागर कपासन	

2019 में चित्तौडगढ़ के तीनों खण्डों में 100 टन से अधिक अफीम का उत्पादन हुआ। प्रथम खण्ड में 35,820 कि.ग्रा. अफीम जिसका मूल्य 6 करोड़ 13 लाख रुपये, द्वितीय खण्ड में 32,540 कि.ग्रा. व मूल्य 5 करोड़ 95 लाख 94 हजार रुपये तथा तृतीय खण्ड में 38,800 कि.ग्रा. व मूल्य 6 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये था। लेकिन 2020-21 में किसानों जारी अनुज्ञप्ति में कमी तथा अफीम नीति में प्रति रकबे में उत्पादन की सीमा निर्धारित करने से किसानों के अफीम पट्टे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 2019-20 व 2020-21 में अनुज्ञप्तिधारी किसानों की संख्या :-

वर्ष	खण्ड	अनुज्ञापिधारी किसानों की संख्या
2019-20	प्रथम खण्ड	4550
	द्वितीय खण्ड	4090
	तृतीय खण्ड	5081
2020-21	प्रथम खण्ड	4320
	द्वितीय खण्ड	3696
	तृतीय खण्ड	3991

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2020-21 में 2019-20 की तुलना में नारकोटिक्स विभाग द्वारा अध्ययन के क्षेत्र में विभिन्न खण्डों के अनुज्ञापिधारी किसानों की संख्या में कमी आयी है। अफीम उत्पादन का अध्ययन क्षेत्र पर आर्थिक-सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव अफीम पर समय समय पर जारी अफीम नीति का किसानों की आय, लाइसेंस व रकबे के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा ही अफीम की खरीद से कृषक की आय की सुनिश्चिता रहती है। इससे अफीम कृषकों की आर्थिक स्थिति अन्य कृषकों की तुलना में अच्छी है। अफीम कृषक सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित एवं साधन सम्पन्न होते हैं। इसी साख के कारण इन्हें कृषि क्षेत्र व अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण या वित्त आसान शर्तों में उपलब्ध हो जाता है। जिससे अफीम कृषकों ने आधारभूत आगतों जैसे सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि का उपयोग कर अफीम की कृषि को विकसित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं अफीम कृषकों द्वारा अधिक श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है अतः अफीम की कृषि अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करती है। लेकिन प्रतिवर्ष जारी अफीम नीति व उसमें होने वाले परिवर्तनों का कृषकों की आय व अनुज्ञापि प्राप्त पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 2019 में जारी अफीम नीति में प्रति हेक्टेयर 5.9 कि.ग्राम अफीम उत्पादन की शर्त रखी गयी व इसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है। उक्त निश्चित मात्रा से कम उत्पादन की स्थिति में कृषकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तीन वर्षों (2017, 2018, 2019) में अध्ययन क्षेत्र में 15000 किसान लाइसेंस गँवा चुके हैं। अतः इसका नकारात्मक प्रभाव कृषकों पर पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के तीनों खण्डों में अफीम कृषकों व शेष कृषकों की आय के स्तर में बड़ा अन्तर अनुसंधान से पता चला जो क्षेत्र में प्रादेशिक असमानता व सामाजिक तनाव का कारण भी है। अफीम की खेती औषधी उपयोग के लिए की जाती है लेकिन यह एक मादक पदार्थ भी है जिससे इसकी तस्करी होती है जो कि गैर कानूनी है। लेकिन तस्करी से प्रति कि.ग्राम से लाखों की आय होती है जो अध्ययन क्षेत्र में अपराध व सामाजिक तनाव का कारण है। अफीम की तस्करी ने तंत्र को भी भ्रष्ट कर दिया है जैसा समय-समय पर अखबारों में आता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र की मृदा की उर्वरता अफीम की कृषि के कारण तेजी से घटी है तथा पक्षियों द्वारा अफीम के सेवन से इनकी संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा अध्ययन क्षेत्र की जैव-विविधता में कमी आयी है। अतः शोध का निष्कर्ष निकला है कि अफीम में संलग्न कृषकों की आय, अन्य कृषकों से अधिक है। आय में विभिन्नता ने प्रादेशिक असमानता व सामाजिक तनाव को बढ़ाया है। शोध सुझाव में अफीम नीति को अधिक व्यवहारिक बनाया जाये तथा भ्रष्ट तंत्र पर नियन्त्रण कर तस्करी को रोका जाना आवश्यक है।

### सन्दर्भ सूची-

1. राठौड़ जी.एस. (1997)-“तुषारपात का रासायनिक नियंत्रण एवं अफीम की दो किस्मों के निष्पादन पर प्रक्षेत्र खाद के उपयोग का प्रभाव”
2. राजपूत वी.एस. (1977)-“चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेडा पंचायत समिति में अफीम उत्पादन तकनीकी ग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक”
3. रिपोर्ट (2009, 2010, 2018, 2019, 2020)-नारकोटिक्स विभाग, भारत सरकार
4. भट्टाचार्य आर (2007)-“द गोल्डन ट्राईगल ऑफ अफगान ओपियम लेशन फार अफगानिस्तान
5. डॉंगी आर.सी. (2004)-“राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम उत्पादकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं बाधाओं को चिन्हित करना”
6. नारायण बारैठ-संवाददाता बी.बी.सी. जयपुर 2 जून 2010